e-ISSN:2582 - 7219

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 4, Issue 8, August 2021

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 5.928

International Journal Of Multidisciplinary Research In Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408026 |

भारत में पंचायती राज प्रणाली: अवसर एवं चुनौतियाँ

Shaivendra Kumar Vyas

Assistant Professor, Department of Public Administration, S.B.P. Govt. College, Dungarpur, Rajasthan, India

सार: पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखरेख करती है। संघ में सरकार की शक्तियाँ और कार्य दो सरकारों के बीच विभाजित होते हैं। भारत में यह केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें हैं।

I. परिचय

पंचायती राज (पाँच अधिकारियों की परिषद) शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत [1] में गाँवों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है ।

इसमें पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई) शामिल हैं जिनके माध्यम से गाँवों की स्वशासन को साकार किया जाता है। [2] उन्हें "आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय को मजबूत करना और ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन" का काम सौंपा गया है। [2]

भारतीय संविधान का भाग IX पंचायतों से संबंधित संविधान की धारा है। [3] [4] यह निर्धारित करता है कि दो मिलियन से अधिक निवासियों वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पीआरआई के तीन स्तर हैं:

- गांव स्तर पर ग्राम पंचायत
- ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति (ब्लॉक समिति, मंडल परिषद) , और[1,2,3]
- जिला स्तर पर जिला पंचायत (जिला परिषद) । [2]

दो मिलियन से कम निवासियों वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पीआरआई के केवल दो स्तर हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं और यह वह संगठन है जिसके माध्यम से गांव के निवासी स्थानीय सरकार में सीधे भाग लेते हैं। सभी स्तरों पर पंचायतों के सदस्यों के लिए चुनाव हर पाँच साल में होते हैं। संघीय कानून के अनुसार, पंचायतों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों को सामान्य आबादी के समान अनुपात में शामिल किया जाना चाहिए और सभी सीटों और अध्यक्ष पदों में से कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। कुछ राज्यों ने महिलाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुपात को बढ़ाकर आधा कर दिया है। [2]

2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायत का उद्घाटन किया। यह दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर चुना गया था। गांधी पंचायती राज के माध्यम से ग्राम स्वराज चाहते थे। [5] [6] 1992 में 73वें संविधान संशोधन के साथ इस प्रणाली को संशोधित किया गया। [7] [8] [9]

भारत में, पंचायती राज अब एक शासन प्रणाली के रूप में कार्य करता है जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन की मूल इकाइयाँ हैं । वर्तमान में, पंचायती राज प्रणाली नागालैंड , मेघालय और मिज़ोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है । [10]

इतिहास

भारत में पंचायती राज की उत्पत्ति वैदिक काल (1700 ईसा पूर्व) से हुई है। वैदिक काल से ही देश में गाँव (ग्राम) को क्षेत्रीय स्वशासन के लिए बुनियादी इकाई माना जाता है। [11]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408026 |

नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश के पास खुली पंचायत

महात्मा गांधी ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था की नींव के रूप में पंचायती राज की वकालत की, सरकार के एक विकेंद्रीकृत रूप के रूप में जिसमें प्रत्येक गांव अपने मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। [12] [13] इस तरह के दृष्टिकोण के लिए शब्द ग्राम स्वराज ("ग्राम स्वशासन") था। इसके बजाय, भारत ने सरकार का एक अत्यधिक केंद्रीकृत रूप विकसित किया। [14] हालाँकि, इसे स्थानीय स्तर पर कई प्रशासनिक कार्यों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा नियंत्रित किया गया है, जिससे निर्वाचित ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया गया है। पारंपरिक पंचायती राज प्रणाली, जिसकी कल्पना गांधी ने की थी, और 1992 में भारत में औपचारिक रूप से अपनाई गई प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। [8]

जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया। यह दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर चुना गया था। गांधी पंचायती राज के माध्यम से ग्राम स्वराज चाहते थे। [5] राजस्थान इसे लागू करने वाला पहला राज्य था। नेहरू ने दशहरा के अवसर पर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का उद्घाटन किया । यह व्यवस्था धीरे-धीरे पूरे भारत में स्थापित हो गई। [6] 1992 में 73वें संविधान संशोधन के साथ इस प्रणाली को संशोधित किया गया। [8] [9]

बलवंत राय मेहता समिति , संसद सदस्य बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में , सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) के काम की जांच करने और उनके काम को बेहतर बनाने के उपाय सुझाने के लिए जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी। समिति की सिफारिश जनवरी 1958 में एनडीसी द्वारा लागू की गई, और इसने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को शुरू करने का मंच तैयार किया। समिति ने 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की योजना की स्थापना की सिफारिश की, जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा। इसके परिणामस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई: गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।[4,5,6]

24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 लागू हुआ। 24 दिसंबर 1996 से यह संशोधन आठ राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों तक विस्तारित किया गया: आंध्र प्रदेश , गुजरात , हिमाचल प्रदेश , महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश , ओडिशा और राजस्थान । इस संशोधन में आर्थिक विकास योजनाओं और सामाजिक न्याय की तैयारी के साथ-साथ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में कार्यान्वयन के लिए पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल हैं, और उचित कर, शुल्क, टोल और शुल्क लगाने और एकत्र करने की क्षमता भी शामिल है। [15] अधिनियम का उद्देश्य दो मिलियन से अधिक आबादी वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली प्रदान करना, हर पाँच साल में नियमित रूप से पंचायत चुनाव कराना, अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना, पंचायतों की वित्तीय शक्तियों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करना और एक जिला योजना समिति का गठन करना है। [16]

II. विचार-विमर्श

4-स्तरीय पंचायत प्रणाली

4 -स्तरीय पंचायत प्रणाली [बीएन] का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी के जन्मदिन (2 अक्टूबर) पर वर्ष 1964 में पश्चिम बंगाल जिला परिषद अधिनियम 1963 के पारित होने से हुआ था। इसमें शामिल थे

1. ग्राम पंचायतें 4 वर्ष की अवधि के लिए ग्रामीणों द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों से बनी होती हैं
2. स्थानीय पंचायतें निर्वाचित सरपंचों और ग्रामीणों द्वारा सीधे 4 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए प्रतिनिधियों से बनी होती हैं,
3. स्थानीय परिषदों में उस सामुदायिक विकास खंड का खंड विकास अधिकारी , उस खंड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय पंचायतों के सभी प्रमुख, उस खंड के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक स्थानीय पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने गए स्थानीय पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, स्थानीय लोकसभा सांसद, जो किसी भी मंत्री पद पर नहीं है, स्थानीय विधायक, जो किसी भी मंत्री पद पर नहीं है, एक राज्यसभा सांसद जो उस खंड का निवासी है और उसके पास कोई मंत्री पद नहीं है, एक एमएलसी जो उस खंड का निवासी है और उसके पास कोई मंत्री पद नहीं है, राज्य सरकार द्वारा नामित 2 महिला सदस्य, राज्य सरकार द्वारा

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408026 |

नामित एससी , एसटी और ओबीसी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 सदस्य और ग्रामीण विकास में अनुभवी 2 सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोक्त सदस्यों द्वारा चुना गया हो

4. जिला परिषदों में उस जिले के उप -विभागों के प्रभारी उप-विभागीय अधिकारी , राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला पंचायत अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नामित एक सिविल सेवक, उस जिले के अंतर्गत सभी स्थानीय परिषदों के अध्यक्ष, उस जिले के प्रत्येक उप-विभाग के सरपंचों द्वारा चुने गए 2 सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामित एक स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष या महापौर , जिला स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा नामित 2 महिला सदस्य और विधायक और सांसद (जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले और उसी जिले के निवासी दोनों) शामिल होते हैं, जिनके पास 4 वर्ष की अवधि के लिए कोई मंत्री पद नहीं होता है।[7,8,9]

त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली

त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का उद्घाटन जून 1973 में पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम द्वारा किया गया था।

1. ग्राम पंचायतें
2. पंचायत समितियां और
3. जिला पंचायतें

नामकरण

भारत के विभिन्न भागों में, बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण पंचायती राज संस्थाओं के स्तरों के अलग-अलग नाम हो सकते हैं। हालाँकि, वे आम तौर पर गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रकृति में समान होते हैं। [17]

जिला परिषद;

जिला परिषद, जिला परिषद, जिला पंचायत, जिला पंचायत, आदि।

ब्लॉक पंचायत;

पंचायत समिति, पंचायत संघ, मंडल परिषद, मंडल प्रजा परिषद, आंचलिक पंचायत, जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तालुका पंचायत, आदि।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत, गाँव पंचायत, आदि।

चुनाव

पंचायती राज के सभी स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, तथा मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष/अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ग्राम स्तर पर अध्यक्ष/अध्यक्ष का चुनाव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। कुछ राज्य ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को चुनने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य अप्रत्यक्ष चुनाव (सदस्यों में से चुने गए) का उपयोग करते हैं।

प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व एक निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। ये सदस्य पंचायत परिषद का गठन करते हैं। कुछ राज्यों में, ब्लॉक या जिला स्तर पर पदेन सदस्य होते हैं जो निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, जैसे विधायक , सांसद आदि। [18]

अवधि

सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनके चुनाव संबंधित राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किये जाते हैं ।

सीटों का आरक्षण

पंचायती राज संस्थाओं में सीटों का आरक्षण समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। इन आरक्षणों में आमतौर पर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं के लिए सीटें शामिल होती हैं। जनसांख्यिकीय कारकों और सामाजिक विचारों के आधार पर आरक्षित सीटों का प्रतिशत राज्य दर राज्य अलग-अलग होता है।[10,11,12]

ग्राम पंचायत सभा

सरपंच (पांच सदस्यों का मुखिया) इसका निर्वाचित मुखिया होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को मतदान-योग्य गांव की आबादी द्वारा सीधे पांच साल की अवधि के लिए चुना जाता है। [19] ग्राम पंचायत अध्यक्ष, जिसे सरपंच के रूप में भी जाना जाता है, अक्सर सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408026 |

पंचायत में निर्वाचित स्थायी समितियाँ काम करती हैं, जो वित्त, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष की अध्यक्षता में तीन से पाँच सदस्य होते हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व और विशेषज्ञता सुनिश्चित करते हैं।

ब्लॉक स्तरीय पंचायत या पंचायत समिति

कोट्टायम जिले में पंचायत अध्यक्ष चुने गए . [20]

जिस तरह भारत के विभिन्न भागों में तहसील को अन्य नामों से जाना जाता है, खास तौर पर मंडल और तालुका , उसी तरह ब्लॉक पंचायत के नामकरण में भी कई तरह की विविधताएँ हैं। उदाहरण के लिए, इसे आंध्र प्रदेश में मंडल प्रजा परिषद , गुजरात और कर्नाटक में तालुका पंचायत और महाराष्ट्र में पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है । सामान्य तौर पर, ब्लॉक पंचायत का स्वरूप ग्राम पंचायत जैसा ही होता है, लेकिन इसका स्तर थोड़ा ऊंचा होता है।

रचना

ब्लॉक पंचायत में सदस्यता अधिकतर पूर्व-सरकारी होती है ; इसमें शामिल हैं: पंचायत समिति क्षेत्र के सभी सरपंच (ग्राम पंचायत अध्यक्ष), क्षेत्र के सांसद और विधायक, उप-विभाग के उप-जिला अधिकारी (एसडीओ), सह-चयनित सदस्य (एससी, एसटी और महिलाओं के प्रतिनिधि), सहयोगी सदस्य (क्षेत्र का एक किसान, सहकारी समितियों का एक प्रतिनिधि और विपणन सेवाओं से एक), और कुछ निर्वाचित सदस्य। हालाँकि, केरल में , ब्लॉक पंचायत के सदस्य सीधे चुने जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य होते हैं।

पंचायत समिति का चुनाव पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है और इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष करते हैं। [21]

व्यवहार में प्रणाली

पंचायतें वर्षों से खुद को आर्थिक रूप से बनाए रखने के लिए संघीय और राज्य अनुदानों पर निर्भर रही हैं। पंचायत परिषद के लिए अनिवार्य चुनावों की अनुपस्थिति और सरपंच की कम बैठकों ने ग्रामीणों तक सूचना के प्रसार को कम कर दिया है, जिससे राज्य विनियमन अधिक हो गया है। [22] कई पंचायतें विभिन्न निकायों के बीच सहयोग और भारत में पहले से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की राजनीतिक लामबंदी के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही हैं। कई पंचायतों को ग्रामीणों की भागीदारी के लिए साक्षरता की बाधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश विकास योजनाएँ कागज़ पर ही रहती हैं। हालाँकि, पंचायती राज प्रणाली से जुड़े घरों में स्थानीय मामलों में भागीदारी में वृद्धि देखी गई है। [23] पंचायत परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति ने भी महिलाओं की भागीदारी में पर्याप्त वृद्धि की है और विकास के फ़ोकस को और अधिक घरेलू मुद्दों को शामिल करने के लिए आकार दिया है। [24]

1992 में, 73वां संशोधन पारित किया गया, जिसने पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका को बदल दिया। [२५] 73वें संशोधन ने बुनियादी ग्राम परिषदों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण स्थापित किया। इस आरक्षण से स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिलाएं अब विभिन्न पदों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में सेवा कर रही हैं, जिनमें सरपंच (ग्राम प्रधान) और पंचायत सदस्य शामिल हैं। महिलाओं ने सरकार की महिलाओं से अपेक्षाओं का जवाब देने के लिए पंचायत में अपनी सकारात्मक और प्रबुद्ध सोच का भी प्रदर्शन किया। उनके परिवारों की सहायक कार्रवाइयां महिलाओं को हर पीआरआई (भारत में पंचायती राज) बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। भले ही नौकरशाही पूरी तरह पुरुष प्रधान थी, गांधीजी को उम्मीद थी कि पंचायती राज एक स्वतंत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा हो सकती है। उदारवाद के प्रवर्तक के रूप में [26] 73वें संशोधन का भी विरोध किया गया क्योंकि सीटों के आरक्षण का मतलब था कि उच्च जाति के लोगों को राजनीतिक सशक्तिकरण प्रणाली में हाशिये की जाति की महिलाओं को स्वीकार करना होगा। अप्रत्यक्ष रूप से, यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है जब सरकार जमीनी स्तर की पंचायतों को धन समर्पित करती है जहाँ नौकरशाही चैनलों द्वारा संसाधनों और धन का शोषण किया जाता है[13,14,15]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408026 |

III. परिणाम

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस) भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। [1] [2]

पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 के माध्यम से संवैधानिक रूप दिया गया। यह विधेयक 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा और 23 दिसंबर 1992 को राजसभा द्वारा पारित किया गया। बाद में इसे 17 राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया गया और 23 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ।

फिर, भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया। [3] उन्होंने उल्लेख किया कि यदि पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई) ठीक से काम करती हैं और स्थानीय लोग विकास प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो माओवादी खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। [3]

24 अप्रैल 2015 को निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में निर्वाचित अपनी पत्नियों के काम पर अनुचित प्रभाव डालने वाली "महिला सरपंचों के पतियों" या "सरपंच पति" की प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया ।

भारत में स्थानीय सरकार राज्य के स्तर से नीचे का सरकारी अधिकार क्षेत्र है । स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि कस्बों, गांवों और ग्रामीण बस्तियों के निवासी वे लोग हैं जो स्थानीय परिषदों और उनके प्रमुखों को चुनते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए अधिकृत करते हैं। भारत एक संघीय गणराज्य है जिसमें सरकार के तीन क्षेत्र हैं: संघ , राज्य और स्थानीय। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन स्थानीय सरकारों को मान्यता और संरक्षण देते हैं और इसके अलावा प्रत्येक राज्य का अपना स्थानीय सरकार कानून है। [1] 1992 से, भारत में स्थानीय सरकार दो अलग-अलग रूपों में होती है। संविधान के 74वें संशोधन में शामिल शहरी इलाकों [2] में नगर पालिका है, लेकिन वे अपनी शक्तियां अलग-अलग राज्य सरकारों से प्राप्त करते हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों की शक्तियों को संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था के तहत औपचारिक रूप दिया गया है। [3]
भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित स्थानीय शासन निकायों को शहरी क्षेत्रों में " नगरपालिका " (संक्षिप्त रूप में "एमसी") और ग्रामीण क्षेत्रों में " पंचायती राज संस्थान (पीआरआई)" (बस "पंचायत" कहा जाता है) कहा जाता है। जनसंख्या के आधार पर 3 प्रकार की नगरपालिकाएँ हैं (राज्य दर राज्य मापदंड अलग-अलग हैं), 1 मिलियन से अधिक आबादी वाला नगर निगम (नगर निगम), 25,000 से अधिक और 1 मिलियन से कम आबादी वाली नगर परिषद (नगर पालिका), और 10,000 से अधिक और 25,000 से कम आबादी वाली नगर समिति (नगर पंचायत)। संविधान यह परिभाषित नहीं करता है कि वास्तव में बड़ा या छोटा शहरी क्षेत्र या ग्रामीण से शहरी में संक्रमण का क्षेत्र क्या होगा। यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वे अपने स्वयं के मानदंड तय करें। अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि जनसंख्या के अलावा, अन्य मापदंडों जैसे जनसंख्या का घनत्व, गैर-कृषि रोजगार में जनसंख्या का प्रतिशत, वार्षिक राजस्व सृजन आदि को राज्यों द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीआरआई में पंचायतों के 3 पदानुक्रम हैं, गाँव स्तर पर ग्राम पंचायतें , ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायतें । [4]

पंचायतें भारत के 5.8 लाख (580,000) से अधिक गांवों में से लगभग 96% और ग्रामीण आबादी के लगभग 99.6% को कवर करती हैं। 2020 तक, पंचायत के सभी स्तरों पर लगभग 3 मिलियन निर्वाचित प्रतिनिधि थे, जिनमें से लगभग 1.3 मिलियन महिलाएँ हैं। ये सदस्य 2.4 लाख (240,000) से अधिक ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं , लगभग 6,672 ब्लॉक स्तर पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत समितियाँ और जिला स्तर पर 500 से अधिक जिला परिषदें हैं। [5] 2013 के स्थानीय चुनाव के बाद, 37.1% पार्षद महिलाएँ थीं, और 2015/16 में स्थानीय सरकारी व्यय कुल सरकारी व्यय का 16.3% था[16,17,18]

इतिहास
मुद्दों के अध्ययन के लिए समितियाँ
भारत में स्थानीय शासन के कार्यान्वयन के लिए मुद्दों का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया।

बलवंत राय मेहता समिति (1957)
1957 में बलवंत राय मेहता की अगुआई में एक समिति ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का अध्ययन किया और इस बात का मूल्यांकन किया कि आंदोलन स्थानीय पहलों का उपयोग करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार की प्रक्रिया में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों का निर्माण करने में किस हद तक सफल रहा है। समिति

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408026 |

ने माना कि सामुदायिक विकास तभी गहरा और स्थायी होगा जब समुदाय नियोजन, निर्णय लेने और कार्यान्वयन प्रक्रिया में शामिल होगा। [6] सुझाव इस प्रकार थे: [7]

- निर्वाचित स्थानीय निकायों की शीघ्र स्थापना और उन्हें आवश्यक संसाधन, शक्ति और अधिकार का हस्तांतरण,
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल इकाई ब्लॉक/समिति स्तर पर थी क्योंकि स्थानीय निकाय का अधिकार क्षेत्र न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा। प्रशासन की दक्षता और मितव्ययिता के लिए ब्लॉक काफी बड़ा था और नागरिकों में भागीदारी की भावना को बनाए रखने के लिए काफी छोटा था,
- ऐसे निकाय को सरकार या सरकारी एजेंसियों द्वारा बहुत अधिक नियंत्रण से विवश नहीं किया जाना चाहिए,
- निकाय का गठन ग्राम पंचायतों से अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा पांच वर्षों के लिए किया जाना चाहिए,
- इसके कार्यों में कृषि के सभी पहलुओं का विकास, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना आदि शामिल होना चाहिए।
- पेयजल, सड़क निर्माण आदि जैसी सेवाएं, और
- उच्च स्तरीय निकाय, जिला परिषद, सलाहकार की भूमिका निभाएगी।

अशोक मेहता समिति (1977)

पंचायती राज संस्था ने अपेक्षित लोकतांत्रिक गति विकसित नहीं की और ग्रामीण विकास की जरूरतों को पूरा करने में विफल रही। इस तरह के परिणाम के लिए कई कारण हैं, जिनमें स्थानीय स्तर की संस्थाओं के साथ सत्ता और संसाधनों को साझा करने के लिए राज्य स्तर पर राजनीतिक और नौकरशाही प्रतिरोध, कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बड़े हिस्से पर स्थानीय अभिजात वर्ग का वर्चस्व, स्थानीय स्तर पर क्षमता की कमी और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी शामिल है।

पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के उपायों की जांच और सुझाव देने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। समिति को पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकास की एक प्रभावी विकेन्द्रीकृत प्रणाली विकसित करनी थी। उन्होंने निम्नलिखित सिफारिशें कीं: [8]

- जिला एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई है जिसके लिए योजना, समन्वय और संसाधन आवंटन संभव है और तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध है,
- पंचायती राज संस्थाएं दो स्तरीय प्रणाली है, जिसके आधार पर मंडल पंचायत और शीर्ष पर जिला परिषद है।
- पंचायती राज संस्थाएं अपने पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्वयं योजना बनाने में सक्षम हैं।
- जिला नियोजन में शहरी-ग्रामीण सातत्य का ध्यान रखा जाना चाहिए,
- पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व,
- पीआरआई का चार वर्ष का कार्यकाल,
- चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी,
- किसी भी वित्तीय हस्तांतरण को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए

जिला स्तर पर अधिकांश विकास कार्य पंचायतों द्वारा किए जाएंगे।

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने इस रिपोर्ट के आधार पर नए कानून पारित किए। हालांकि, राज्य स्तर पर राजनीति में उतार-चढ़ाव ने इन संस्थाओं को अपनी राजनीतिक गतिशीलता विकसित करने का मौका नहीं दिया।

जीवीके राव समिति (1985)

योजना आयोग द्वारा जी.वी.के. राव समिति की नियुक्ति की गई थी [9] ताकि एक बार फिर पी.आर.आई. के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा सके। समिति का मानना था कि ग्रामीण विकास का समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिसमें पी.आर.आई. को लोगों की समस्याओं से निपटने में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। इसने निम्नलिखित सिफारिशें कीं: [10] –

- पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रभावी संगठन बनने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- जिला स्तर और उससे नीचे के पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य सौंपा जाना चाहिए, और
- खंड विकास कार्यालय को ग्रामीण विकास प्रक्रिया की रीढ़ होना चाहिए।
- जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।
- चुनाव नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए.

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408026 |

यह जीवीके राव समिति का मुख्य विषय है जिस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया।

एल.एम. सिंघवी समिति (1986)
1980 के दशक में लक्ष्मी मल्ल सिंघवी की अगुआई में एक समिति गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य पीआरआई को पुनर्जीवित करने के तरीकों की सिफारिश करना था। ग्राम सभा को विकेंद्रीकृत नगरपालिका का आधार माना गया, और पीआरआई को शासन की ऐसी संस्थाएँ माना गया जो वास्तव में नियोजन और विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगी। इसने सिफारिश की: [11]

- स्थानीय सरकार को संविधान में नया अध्याय शामिल करके संवैधानिक मान्यता, सुरक्षा और संरक्षण दिया जाना चाहिए,
- पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की गैर-भागीदारी।

पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के सुझाव का सरकारिया आयोग ने विरोध किया था, लेकिन 1980 के दशक के अंत में इस विचार ने गति पकड़ी, खासकर दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समर्थन के कारण , जिन्होंने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। 64वां संशोधन विधेयक तैयार किया गया और संसद के निचले सदन में पेश किया गया। लेकिन यह राज्यसभा में असंबद्ध होने के कारण पराजित हो गया। वे आम चुनाव भी हार गए। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा ने 74वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जो नौवीं लोकसभा के भंग होने के कारण अधिनियम नहीं बन सका। नए संविधान संशोधन अधिनियम को तैयार करते समय इन सभी विभिन्न सुझावों और सिफारिशों और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के साधनों पर विचार किया गया।

कानूनी ढांचा
विभिन्न समितियों की चयनित सिफारिशों को लागू करने के लिए निम्नलिखित कानून और संशोधन पारित किए गए।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992)
73वें संशोधन [12] को जन्म देने वाला विचार जमीनी स्तर से दबाव का जवाब नहीं था, बल्कि इस बात की बढ़ती मान्यता थी कि पिछले दशक की संस्थागत पहलों ने कोई परिणाम नहीं दिया है, कि ग्रामीण गरीबी की सीमा अभी भी बहुत बड़ी है और इसलिए सरकार के मौजूदा ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। यह विचार केंद्र और राज्य सरकारों से विकसित हुआ। यह भारत में सरकारी संकटों के समाधान के रूप में पीआरआई को देखने का एक राजनीतिक प्रयास था।

नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1992 में पारित संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य "राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र" स्थापित करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करना था। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं: [13]

- विकेंद्रीकृत शासन के लिए विचार-विमर्श करने वाले निकाय के रूप में ग्राम सभा या ग्राम सभा की परिकल्पना पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में की गई है। संविधान के 73वें संशोधन ने ग्राम सभाओं को अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक लेखा-परीक्षण करने का अधिकार दिया है।
- गांव (ग्राम पंचायत-जीपी), मध्यवर्ती या ब्लॉक (पंचायत समिति-पीएस) और जिला (जिला परिषद-जेडपी) स्तर पर पंचायतों की एक समान त्रिस्तरीय संरचना।
- प्रत्येक स्तर पर पंचायत की सभी सीटें संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव द्वारा भरी जाएंगी।
- प्रत्येक स्तर पर सदस्यता तथा अध्यक्ष पद के लिए कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।
- पंचायतों में कमजोर जातियों और जनजातियों (एससी और एसटी) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सभी स्तरों पर आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- पंचायतों के नियमित और सुचारू चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए, राज्य चुनाव आयोग अधिनियम ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक पांच वर्ष के लिए एक राज्य वित्त आयोग के गठन को सुनिश्चित किया है, ताकि पंचायती राज संस्थाओं के वित्त को मजबूत करने के उपाय सुझाए जा सकें।
- नीचे से ऊपर की ओर नियोजन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति (डीपीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 मदों की सांकेतिक सूची दी गई है। पंचायतों से इन 29 मदों से संबंधित कार्यों की योजना बनाने और क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408026 |

97वां संविधान संशोधन अधिनियम (2011)

डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के अंतर्गत 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के पश्चात सहकारी समितियों को "स्थानीय सरकार" के अंतर्गत लिया गया। भारतीय संविधान का भाग-IX स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिसके अंतर्गत पंचायत राज को परिभाषित किया गया, फिर 74वें संशोधन के पश्चात भाग IX-A को शामिल करके नगर निगम और परिषद को शामिल किया गया और 2011 में संविधान में भाग IX-B को शामिल करके सहकारी समितियों को स्थानीय सरकार में शामिल किया गया।

97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 में निम्नलिखित बातों में संशोधन का प्रावधान किया गया:

1. इसने 'या यूनियनों' शब्द के बाद 'या सहकारी समितियों' शब्दों को जोड़कर अनुच्छेद 19(1)सी में संशोधन किया।
2. इसने संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 43 बी भी जोड़ा, "राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा" और
3. संविधान के भाग IX-A के बाद भाग IX-B जोड़ा गया। भाग IX-B अनुच्छेद 243ZH से अनुच्छेद 243ZT तक विस्तारित किया गया।[19]

IV. निष्कर्ष

स्थानीय शासन संस्थाओं को मोटे तौर पर शहरी और ग्रामीण में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें शहरी निकायों के मामले में जनसंख्या के आकार के आधार पर और ग्रामीण निकायों के मामले में जनसंख्या के आकार और पदानुक्रम के आधार पर उप-विभाजित किया गया है।

शहरी स्थानीय शासन निकाय

3 प्रकार के एम.सी.

भारत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित शहरी स्थानीय शासन निकायों के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं जिन्हें नगरपालिका कहा जाता है और संक्षिप्त रूप में "एमसी" कहा जाता है। इन्हें शहरी बस्ती की आबादी के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। [14]

- नगर निगम , जिसे "नगर निगम" या "सिटी कॉरपोरेशन" भी कहा जाता है , 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का निगम है।
- नगर पालिका परिषदें , जिन्हें "नगर पालिका" या "नगर पालिका परिषद" भी कहा जाता है , 25,000 से अधिक और 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों की होती हैं।
- नगर पालिका समिति , जिसे "नगर परिषद" या "नगर पंचायत" या "नगर पंचायत" या "अधिसूचित क्षेत्र परिषद" या "अधिसूचित क्षेत्र समिति" भी कहा जाता है , जो उस राज्य पर निर्भर करता है जिसमें वे स्थित हैं, ये 10,000 से अधिक और 25,000 से कम आबादी वाले शहर में होते हैं।

नगरपालिका अधिनियम

नगरपालिका अधिनियम शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका सरकारें स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय कानून हैं। ये अधिनियम राज्य के भीतर शहरों के लिए शासन का ढांचा प्रदान करते हैं। चुनाव के नियम, कर्मचारियों की भर्ती और शहरी क्षेत्रों के सीमांकन सहित विभिन्न प्रक्रियाएँ राज्य नगरपालिका अधिनियमों से प्राप्त होती हैं। भारत में लगभग 70 अलग-अलग नगरपालिका अधिनियम देश के शहरों को नियंत्रित करते हैं। आम तौर पर, नगरपालिका अधिनियम तीन प्रकार के होते हैं - राज्यव्यापी सामान्य नगरपालिका अधिनियम, नगर निगमों की स्थापना के लिए अलग अधिनियम और व्यक्तिगत नगर निगमों के लिए विशिष्ट अधिनियम। [15]

एम.सी. के कार्य

भारत में सभी नगरपालिका अधिनियम नगरपालिका सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों, शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान करते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: अनिवार्य और विवेकाधीन।

नगर निगम के अनिवार्य कार्यों में शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक जल की आपूर्ति, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण और रखरखाव, सार्वजनिक सड़कों पर प्रकाश और पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और सीवरों की सफाई, आपत्तिजनक, खतरनाक या अप्रिय व्यापारों और व्यवसायों या प्रथाओं का विनियमन, सार्वजनिक अस्पतालों का रखरखाव या समर्थन, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, सार्वजनिक सड़कों, पुलों और अन्य स्थानों में अवरोधों और उभारों को हटाना, सड़कों का नामकरण और घरों को क्रमांकित करना, कानून और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना आदि शामिल हैं।

नगर निगम के विवेकाधीन कार्यों में क्षेत्रों का निर्धारण, खतरनाक इमारतों या स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना, सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, विश्राम गृहों, कुष्ठरोग गृहों, अनाथालयों और महिलाओं के लिए बचाव गृहों, सार्वजनिक भवनों का निर्माण और रखरखाव, वृक्षारोपण और सड़कों का रखरखाव, निम्न आय वर्ग के लिए आवास, सर्वेक्षण करना, सार्वजनिक स्वागत

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408026 |

समारोह, सार्वजनिक प्रदर्शनियों, सार्वजनिक मनोरंजन का आयोजन, नगरपालिका के साथ परिवहन सुविधाओं का प्रावधान और नगरपालिका कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना शामिल हैं।

शहरी निकायों के कुछ कार्य राज्य एजेंसियों के काम से ओवरलैप होते हैं। संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों सहित नगर पालिका के कार्य राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिए गए हैं। स्थानीय निकायों को अधिनियम द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ, अधिकार और ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए। हालाँकि, अधिनियम ने उन्हें सीधे कोई शक्ति प्रदान नहीं की है और इसके बजाय इसे राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया है। [16] ये सभी नगर निगमों के कार्य हैं

ग्रामीण स्थानीय शासन निकाय
ग्रामीण भारत के गांवों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित स्थानीय शासन निकायों को पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) कहा जाता है जो वैदिक युग की मूल लोकतांत्रिक पंचायत (पांच अधिकारियों की परिषद) प्रणाली पर आधारित हैं। [17] [18]
पीआरआई पंचायतों के 3 पदानुक्रम
दो मिलियन से अधिक निवासियों वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पीआरआई पंचायतों के निम्नलिखित 3 पदानुक्रम मौजूद हैं:

- गांव स्तर पर ग्राम पंचायतें
- सामुदायिक विकास खंड या मंडल या तालुक स्तर पर पंचायत समिति या मंडल परिषद या ब्लॉक पंचायत या तालुक पंचायत और
- जिला स्तर पर जिला परिषद / जिला पंचायत [18]

पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें गांव, तालुका और जिला स्तर पर निर्वाचित निकाय होते हैं। आधुनिक व्यवस्था आंशिक रूप से पारंपरिक पंचायत शासन पर, आंशिक रूप से महात्मा गांधी के दृष्टिकोण पर और आंशिक रूप से स्थानीय स्वायत्तता की एक हद तक अत्यधिक केंद्रीकृत भारतीय सरकारी प्रशासन को सुसंगत बनाने के लिए विभिन्न समितियों के काम पर आधारित है। [19] इसका उद्देश्य स्थानीय सरकार में लोगों की अधिक भागीदारी और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन करना था। हालाँकि, 2015 तक, पूरे भारत में कार्यान्वयन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इरादा यह है कि प्रत्येक गाँव या गाँवों के समूह के लिए एक ग्राम पंचायत , एक तहसील स्तर की परिषद और जिला स्तर पर एक जिला पंचायत हो।

भारत में, पंचायत राज संस्थाओं का नामकरण विभिन्न राज्यों में भिन्न है। गाँव के स्तर पर, पंचायत राज संस्थाओं को आमतौर पर अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायतों के रूप में जाना जाता है। ये ग्राम पंचायतें या ग्राम पंचायतें जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन और शासन के लिए जिम्मेदार हैं। ब्लॉक या तहसील स्तर की पंचायत राज संस्थाओं को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में उन्हें ब्लॉक पंचायत कहा जाता है, जबकि अन्य में उन्हें पंचायत समिति, पंचायत यूनियन और मंडल परिषद कहा जाता है। विशिष्ट नाम राज्य दर राज्य अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है – ब्लॉक या तहसील स्तर पर विकास और कल्याण गतिविधियों की देखरेख करना। जिला स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जिला पंचायत, जिला परिषद, जिला परिषद और जिला पंचायत। [20]

पंचायती राज संस्थाओं के कार्य
भारतीय संविधान के भाग IX में परिभाषित, [21] [22] ये ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के लिए जिम्मेदार हैं जिनमें "आर्थिक विकास, और सामाजिक न्याय को मजबूत करना" शामिल है। [18]

भारत के राज्यों के अनुसार स्थानीय निकाय
भारत का संविधान पंचायतों को स्थानीय शासन की संस्थाओं के रूप में देखता है। हालाँकि, भारत की राजनीति के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए, पंचायतों को दी जाने वाली अधिकांश वित्तीय शक्तियाँ और अधिकार संबंधित राज्य विधानसभाओं के विवेक पर छोड़ दिए गए हैं। नतीजतन, पीआरआई में निहित शक्तियाँ और कार्य राज्य दर राज्य अलग-अलग होते हैं। ये प्रावधान प्रतिनिधि और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक साथ जोड़ते हैं और इनसे भारत में लोकतंत्र के विस्तार और गहनता की उम्मीद है। इसलिए, पंचायतों ने भारत की संस्कृति के भीतर एक संस्था से संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की यात्रा की है।

जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता छीनकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण की मुख्य अवधारणा यह है कि स्थानीय स्तर पर कई समस्याओं और मामलों को बेहतर ढंग से हल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर, लोग सीधे निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। यह लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और लोगों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। 1992 में, विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को आमतौर पर "पंचायती राज संस्थाओं (PRI)" के रूप में जाना जाता है। यह स्थानीय सरकार संरचना जिला स्तर तक फैली हुई है। शहरी स्थानीय सरकार को आमतौर पर "शहरी स्थानीय निकाय" (ULB) के रूप में जाना जाता है। नगर निगम, नगर परिषद और

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408026 |

नगर पंचायतें स्थानीय मामलों, जैसे कि बुनियादी ढाँचे के विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार शहरी स्थानीय निकायों के उदाहरण हैं। [23]

स्थानीय सरकारों को विभिन्न सरकारी संस्थानों का संचालन सौंपा गया है, जो पहले राज्य सरकार के नियंत्रण में थे। इन हस्तांतरणों में सरकारी जिला अस्पताल शामिल हैं, जो अब जिला पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तालुक या उप-जिला अस्पताल, जो अब ब्लॉक पंचायतों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, और तालुक मुख्यालय अस्पताल, जो अब संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी हैं। इसी तरह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख अब ब्लॉक पंचायतों या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का प्रबंधन संबंधित ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कृषि कार्यालय, पशु चिकित्सा अस्पताल, आंगनवाड़ी, मत्स्य पालन कार्यालय और अन्य संबंधित संस्थानों को भी संबंधित स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में, जिला पंचायतों ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों का प्रभार ले लिया है, जबकि संबंधित ग्राम पंचायतें सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। शहरी क्षेत्रों में, उच्चतर माध्यमिक, उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक विद्यालयों सहित सभी सरकारी स्कूलों को शासन और प्रशासन के लिए संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया गया है। स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ स्थानीय मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें बुनियादी ढाँचा विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और शहरी नियोजन, लघु सिंचाई, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु उद्योग, सामाजिक कल्याण, बिजली, खेल और सांस्कृतिक मामले, गरीबी उन्मूलन, आवास आदि शामिल हैं।

कार्य एवं शक्तियाँ;
कुछ कार्य और शक्तियाँ जो पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के विशेष अधिकार क्षेत्र में थीं, उन्हें स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। इन कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढाँचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। इन कार्यों को विकेंद्रीकृत करके, स्थानीय सरकारों को ऐसे निर्णय लेने और नीतियों को लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ जो स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी हैं।

प्रशासनिक प्राधिकारी;
विकेंद्रीकरण में स्थानीय सरकारों को प्रशासनिक अधिकार प्रदान करना शामिल था। इसका मतलब था कि स्थानीय सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन और देखरेख करने की शक्ति प्राप्त हुई। वे स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्त और प्रबंधित कर सकते थे, विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित कर सकते थे और सार्वजनिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित कर सकते थे। प्रशासनिक अधिकार के इस हस्तांतरण का उद्देश्य स्थानीय सरकारों की प्रभावी रूप से शासन करने की क्षमता को बढ़ाना था।

वित्तीय संसाधन;
कार्यों और शक्तियों के साथ-साथ वित्तीय संसाधन भी स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित किए गए। इसमें उन्हें कर राजस्व, अनुदान और सरकार के उच्च स्तरों से धन का हिस्सा प्रदान करना शामिल था। विचार यह था कि स्थानीय सरकारों को अपनी ज़िम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाएँ। वित्तीय विकेंद्रीकरण का उद्देश्य सरकार के उच्च स्तरों पर निर्भरता को कम करना और वित्तीय मामलों में स्थानीय निर्णय लेने को बढ़ावा देना था।

संस्थागत ढांचा;
विकेंद्रीकरण को सुगम बनाने के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने क्रमशः ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इन संशोधनों ने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और नगरपालिका और शहर और कस्बे के स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की स्थापना को अनिवार्य बना दिया।

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना ने विकेन्द्रीकृत शासन के लिए एक ढांचा प्रदान किया तथा जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा दिया।[20]

संदर्भ

1. "भारत में पंचायती राज संस्थाएँ" . India.gov.in .
2. ^ "पंचायती राज संस्थाओं के बुनियादी आँकड़े" (पीडीएफ) । पंचायती राज मंत्रालय। 2019. 7 अप्रैल 2020 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 28 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408026 |

3. ^ रेणुकादेवी नागशेट्टी (2015)। "IV. कर्नाटक और गुलबर्गा जिले में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और संगठनात्मक पहलू"। भारत में पंचायत राज संस्थाओं के कामकाज में समस्याएँ और चुनौतियाँ। गुलबर्गा जिला पंचायत का एक केस स्टडी (पीएचडी)। पी. 93. एचडीएल : 10603/36516 । मूल से 13 अक्टूबर 2017 को संग्रहीत (पीडीएफ) । 28 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
4. ^ "कार्यवाही का रिकॉर्ड। रिट याचिका (सिविल) संख्या 671/2015" (पीडीएफ) । विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा वेबसाइट "भारत पर्यावरण पोर्टल" । भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 2015. पी। 3. मूल से 28 अक्टूबर 2020 को संग्रहीत (पीडीएफ) । 28 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
5. ↑ शर्मा, शकुंतला (1994). ग्रास रूट पॉलिटिक्स और पंचायती राज . डीप एंड डीप पब्लिकेशन. पृ. 131.
6. ^ सिंह, सूरत (2004)। भारत में विकेंद्रीकृत शासन: मिथक और वास्तविकता । डीप एंड डीप प्रकाशन। पी. 74. आईएसबीएन 978-81-7629-577-2.
7. ^ "भारत की ग्रामीण स्थानीय सरकार की संरचना" । 3 जनवरी 2020 को लिया गया ।
8. ^ सिंह, विजेंद्र (2003)। "अध्याय 5: पंचायती राज और गांधी"। पंचायती राज और ग्राम विकास: खंड 3, पंचायती राज प्रशासन पर परिप्रेक्ष्य । लोक प्रशासन में अध्ययन। नई दिल्ली: सरूप एंड संस। पीपी. 84-90. आईएसबीएन 978-81-7625-392-5.
9. ↑ "गाँवों में रहना | डी+सी - विकास + सहयोग" .
10. ^ आज, तेलंगाना (22 फरवरी 2020)। "राय: पंचायतों को और अधिक प्रभावी बनाएं" । तेलंगाना टुडे । 26 जून 2020 को लिया गया ।
11. ↑ पंचायती राज: अरुणाचल प्रदेश में जमीनी स्तर की गतिशीलता, पृष्ठ 13, एपीएच प्रकाशन, 2008, प्रताप चंद्र स्वैन
12. ↑ सिसोदिया, आर.एस. (1971). "गांधीजी का पंचायती राज का दृष्टिकोण"। पंचायत और इंसान . 3 (2): 9–10.
13. ^ शर्मा, मनोहर लाल (1987). भारत में गांधी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण . नई दिल्ली: डीप एंड डीप पब्लिकेशन्स. ओसीएलसी 17678104 . हाथी ट्रस्ट की प्रतिलिपि, केवल खोजें
14. ^ हार्डग्रेव, रॉबर्ट एल. और कोचानेक, स्टेनली ए. (2008). भारत : विकासशील राष्ट्र में सरकार और राजनीति (सातवां संस्करण). बोस्टन, मैसाचुसेट्स: थॉमसन/वड्सवर्थ . पृष्ठ 157. आईएसबीएन 978-0-495-00749-4.
15. ↑ भारत 2007, पृष्ठ 696, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
16. ^ "स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था" (पीडीएफ) । Pbrdp.gov.in । 8 अगस्त 2019 को लिया गया ।
17. ^ "पंचायतों की संख्या" . pib.gov.in . 15 मई 2020 को लिया गया .
18. ^ "भारत में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन" (पीडीएफ) .
19. ↑ सीताराम, मुक्काविल्ली (1990). ग्रामीण विकास में नागरिक भागीदारी . मित्तल प्रकाशन. पृ. 34. आईएसबीएन 9788170992271ओसीएलसी 23346237 .
20. ^ "मणि उम्मीदवार कोट्टायम जिला पंचायत अध्यक्ष हैं" । द हिंदू । 25 जुलाई 2019।

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 5.928

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

9710 583 466 | 9710 583 466 | ijmrset@gmail.com

www.ijmrset.com